तक निम्नलिखित राज्यों में प्रत्येक के लिये एक परियोजना स्वीकृत की गई है :—

1. आंध्र प्रदेश
2. गुजरात
3. हरियाणा
4. जम्मू और कश्मीर
5. कर्नाटक
6. केरल
7. महाराष्ट्र
8. पंजाब
9. राजस्थान
10. तमिलनाडु

उपर्युक्त परियोजनायें कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं ।

(ख) और (घ) सरकार ने देश में पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिये जून, 1988 में विकास केन्द्र योजना की घोषणा की थी । 70 विकास केन्द्रों की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है जिनमें से 69 परियोजनाओं का चयन कर लिया गया है । प्राप्त हुई 65 परियोजना रिपोर्टों में से 39 का अंतिम रूप से अनुमोदन कर दिया गया है । ये अनुमोदित 39 केन्द्र कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं । एकीकृत आधारभूत सुविधा विकास योजना लघु तथा अत्यन्त लघु उद्योगों के लिये है, प्रत्येक केन्द्र की परियोजना लागत 5 करोड़ रुपये होगी जिसमें 2 करोड़ रुपये केन्द्रीय अनुदान के रूप में और 3 करोड़ रुपये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) से ऋण के रूप में होंगे । प्रत्येक एकीकृत आधारभूत सुविधा विकास परियोजना की स्थापना 15–20 हैक्टेयर क्षेत्र में की जायेगी । जहां तक विकास केन्द्र योजना का संबंध है यह बड़े, मध्यम और लघु उद्योगों की स्थापना के लिये है । प्रत्येक विकास केन्द्र के लिये लगभग 30 करोड़ रुपये का निवेश होने का अनुमान है जिसमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा बाजार ऋणों की भागीदारी होगी । एकीकृत आधारभूत सुविधा विकास केन्द्रों की स्थापना उन जिलों से भिन्न जिलों में की जायेगी जहां विकास केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं ।

**आयुध कारखानों के कार्यकरण संबंधी प्रतिवेदन**

***74. श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयुध कारखानों के कार्यकरण के संबंध में पिछले सितम्बर में आयुध कारखानों संबंधी बोर्ड, कलकत्ता को प्रस्तुत किये गये दो प्रतिवेदनों का अध्ययन कर लिया है जिनमें से एक प्रतिवेदन मैसर्स बाटलीबाई एंड कम्पनी नामक एक सलाहकार कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसे लागत लेखा और वित्तीय प्रबंधन की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया था तथा दूसरा प्रतिवेदन टाटा कंसलटेंसी सर्विसिज (टी०सी०एस०) द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसे देश में सबसे बड़े इंजीनियरी समूह के पुनरुद्धार के लिये विविधता लाने संबंधी नीति तैयार करने का कार्य सौंपा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो आयुध कारखानों को संपूर्ण रूप से चुस्त-दुरूस्त बनाने तथा उनकी विपणन कुशलताओं को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जा रहे हैं ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :** (क) और (ख) आयुध निर्माणियों में लागत लेखाकरण क्रिया-विधियों और वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों की समीक्षा करने का कार्य मैसर्स बाटली वाई एंड कम्पनी को सौंपा गया था । दिसम्बर, 1994 में प्राप्त कम्पनी की रिपोर्ट पर नई दिल्ली में लागत लेखाकरण एवं मूल्य निर्धारण विषय पर जनवरी, 1995 में हुई संगोष्ठी में विस्तृत रूप से चर्चा की गई थी । आयुध निर्माणी बोर्ड

को वारंट वैधता में कमी करने अस्वीकृत सामग्री के लिये अलग मांग नोट भेजने भंडार खाते के सरलीकरण उपरिशीर्षों के पुनर्वर्गीकरण आदि से संबंधित कुछ सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये अनुदेश जारी कर दिये गये हैं । इस रिपोर्ट में कई अन्य सिफारिशें शामिल हैं जिनकी गहरी संवीक्षा किये जाने की आवश्यकता है । इसके लिये एक कार्यबल गठित किया गया है ।

मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसिज को आयुध निर्माणी बोर्ड द्वारा सिविल बाजार में विविधीकरण के लिये अध्ययन करने एवं योजना तैयार करने का कार्य सौंपा गया था । उनकी रिपोर्टों में गैर-रक्षा ग्राहकों के लिये कुछ उन उत्पादों की पहचान की गई है जिनका निर्माण अतिरिक्त क्षमताओं का उपयोग करके किया जा सकता है । इन मदों में आटोमोबाइल उद्योग, बिजली, क्षेत्र, चीनी उद्योग आदि से संबंधित मदें शामिल हैं । संबद्ध उद्योगों से कुछ मदों के लिये आर्डर प्राप्त हुये हैं । टाटा कंसलटेंसी सर्विसिज के सुझाव पर पांच क्षेत्रीय विपणन केन्द्र खोले गये हैं ताकि गैर-रक्षा ग्राहकों को की जाने वाली बिक्री में वृद्धि की जा सके । पिछले कुछ वर्षों में आयुध निर्माणी बोर्ड की विविधीकरण की दशा में हुई प्रगति काफी अच्छी है और वर्ष 1993–94 में गैर-रक्षा ग्राहकों को की गई बिक्री लगभग 21 प्रतिशत रही है ।

**Joint production of a family car by Benz and TELCO**

*75. SHRI V- HANUMANTHA RAO: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a.) whether Daimler Benz is planning production of a family car with TELCO;

(b) if so, the estimated cost of the car and exact amount of investment expected to flow for the purpose in India during the next two years;

(c) whether the cost of the car is reasonable in comparison to Maruti car, and

(d) if so, how many such cars are expected to be manufactured by the private sector?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI KRISHNA SAHI): (a) TELCO have recently entered into a joint venture with M/s. Daimler Benz for manufacture of 'E' class Mercedes cars in India. Government is not aware of any other proposal front M/s. Daimler Benz for manufacture of any other type of car with TELCO. Manufacture of cars is presently delicensed and therefore does not require approval of Government.

(b) to (d) Do not arise.

**औद्योगिक विकास केन्द्रों को मान्यता**

*76. प्रो० राम बक्ष सिंह वर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, सरकार द्वारा मान्यता प्रदान किए गए औद्योगिक विकास केन्द्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) आगामी एक वर्ष के दौरान कितने केन्द्रों को मान्यता प्रदान की जाएगी तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में भी औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) उद्योगों का क्षेत्रीय छितराव करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पूरे देश में 70 विकास केन्द्रों की स्थापना करने के लिए 1988 में एक योजना घोषित की थी । अब तक 69 केन्द्रों का पता लगाया